

२।

राजस्थान सरकार
कार्मिक(क-3 / शिका) विभाग

क्रमांक:प. 2(157)कार्मिक / क-3 / शिका / 97

जयपुर, दिनांक: ३ APR 2011.

परिपत्र

विषय:- अभियोजन स्वीकृति के प्रकरणों को समयबद्ध रूप से निस्तारित किये जाने के संबंध में।

अभियोजन स्वीकृति के प्रकरणों को समयबद्ध रूप से निस्तारित किये जाने के संबंध में इस विभाग के सम संख्यक परिपत्र दिनांक 24.3.2007 द्वारा जारी निर्देशों की निरन्तरता में निम्नांकित निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए अभियोजन स्वीकृति संबंधी प्रकरणों का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें :—

1. सक्षम प्राधिकारी अभियोजन स्वीकृती के पूर्ण प्रस्ताव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से प्राप्त होने से 4 माह की अवधि के भीतर अभियोजन स्वीकृती प्रसारण के बिन्दु पर प्रकरण का निस्तारण सुनिश्चित करें जैसा कि मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1193/2012 डॉ० सुब्रमेण्यम् खामी बनाम डॉ० मनमोहन सिंह एवं अन्य में पारित निर्णय में निर्दिष्ट किया गया है।
2. संबंधित सक्षम प्राधिकारी प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से कोई स्पष्टीकरण चाहे तो उक्त स्पष्टीकरण की प्रक्रिया भी निर्धारित 4 माह की अवधि में ही पूर्ण करनी होगी।
3. ऐसा ध्यान में लाया गया है कि सरकार द्वारा नियंत्रित निगमों/ बोर्डों में आपराधिक प्रकरणों में प्राईवेट ऐजेन्सी से जांच कराई गयी। अतः स्पष्ट किया जाता है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से अभियोजन स्वीकृती के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर यदि किसी अनुसंधान/ जांच की आवश्यकता समझी जावे तो प्रकरण में जांच किसी भी स्थिति में किसी प्राईवेट ऐजेन्सी/ संस्था से नहीं कराई जावे। जांच अत्यावश्यक समझे जाने पर सक्षम प्राधिकारी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त अन्य राजकीय ऐजेन्सी/ संस्था से ही करावें तथा ऐसी जांच में यदि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से प्राप्त रिपोर्ट से भिन्न तथ्य प्रकट हों तो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को ऐसी जांच से प्राप्त तथ्यों से अवगत कराया जाकर उनका पक्ष भी सुना जावे। किन्तु यह प्रक्रिया भी 4 माह की निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

कृपया उक्त निर्देशों का पूर्णरूपेण पालन करें।

(खेमराज)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राज० जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक/ निजी सचिव, समस्त मा० मंत्रीगण, राज० जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज० जयपुर।
5. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव।
7. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राज० जयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्तगण।
9. समस्त विभागाध्यक्ष(मय जिला कलेक्टर्स)
10. महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज० जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राज० जयपुर।
12. प्रोग्रामर, कार्मिक विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।

(गणपत सिंह गहलोत)
संयुक्त विधि परामर्शी